भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3761

दिनांक 17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

ग्राम संसाधन केन्द्र

†**3761. श्रीमती गीता कोडा:**

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम संसाधन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रस्तावित केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो झारखंड राज्य के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी नहीं, फिलहाल अंतरिक्ष विभाग के पास नए ग्राम संसाधन केंद्र (वीआरसी) स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि वीआरसी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उपग्रह प्रौद्योगिकी की क्षमता को दर्शाने के लिए की गई थी। अंतरिक्ष विभाग / इसरो ने चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों और राज्य सरकार के विभागों के सहयोग से बड़े पैमाने (पायलेट स्केल) पर ग्राम संसाधन केंद्रों (वीआरसी) की स्थापना की थी। ग्राम संसाधन केंद्रों ने विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं जैसे टेलि-हेल्थकेयर, टेलि-एजुकेशन, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, ग्रामीण विद्यार्थियों को कृषि रोजगार मार्गदर्शन संबंधी परामर्श, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान की है ।

वर्ष 2004 से 2013 के दौरान देश भर में उपग्रह कनेक्टिविटी का उपयोग करके 473 ग्राम संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई। संचार क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन के कारण, उपयोगकर्ता अंतरिक्ष संचार के विकल्प के रूप में अन्य कनेक्टिविटी समाधानों को अपना रहे हैं।

वर्ष 2015 के दौरान इसरो की सामाजिक अनुसंधान प्रभाग, विकास और शैक्षिक संचार इकाई द्वारा त्वरित नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से एक अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि 70% प्रतिभागियों ने इसे उपयोगी पाया। देश के उन क्षेत्रों में, जहां अन्य स्थलीय कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां से वीआरसी के लिए यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो अंतरिक्ष विभाग उस पर विचार करने के लिए तैयार है ।

(ख) से (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

*****